



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5141]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940

No. 5141]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

**का.आ. 6398(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1454(अ) के तहत सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय, बंबई को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण महाराष्ट्र है;

और जबकि, श्री एस. एस. अदकार, सिटी सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बॉम्बे, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1785(अ) के तहत उक्त न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1785 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्वारा श्री ए. टी. वानखेड़े, सिटी सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश मुम्बई, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV(भाग-I)(खंड-2)]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2018

**S.O. 6398(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 1454(E) dated the 25<sup>th</sup> June, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of City Civil and Sessions Court, Bombay, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Maharashtra for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri S.S. Adkar, City Civil and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1785(E) dated the 5<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1785(E), dated the 5<sup>th</sup> June, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Bombay, hereby appoints Shri A.T. Wankhede, City Civil and Additional Sessions Judge, Mumbai, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-I)(Vol.-2)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.